

खास-खबरें

मुख्यमंत्री ने दी जन औषधि दिवस की शुभकामनाएं

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को जन औषधि दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य और निरोग जीवन के लिए जन औषधि केंद्र को सौगात दी है। इन केंद्रों पर उपलब्ध हो रही रियायती दरों पर दवाई से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का बेहतर इलाज सुनिश्चित हो रहा है। भारत सरकार की यह पहल देशवासियों के लिए खराब के समान है।

भारतरत्न पं. गोविंद बल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत रत्न, स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पं. गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्र के लिए गोविंद बल्लभ पंत को प्रतिबद्धता और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए देशवासी सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

मप्र बना देश का पहला पूर्ण पेपरलेस और फेसलेस ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम

भोपाल: प्रदेश सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संपदा 2.0 प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों का पूर्णतः पेपरलेस ई-पंजीयन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित यह व्यवस्था नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में शामिल है। प्रदेश में हर वर्ष लगभग 16 लाख दस्तावेजों का पंजीयन किया जाता है, जिससे 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। वेब आधारित संपदा प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग की सुविधा देकर पूरी प्रक्रिया को एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है। संपदा 2.0 के लागू होने के साथ ही मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां दस्तावेजों का पूर्णतः पेपरलेस और डिजिटल पंजीयन संभव हुआ है। इस प्रणाली के जरिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ई-स्टाम्प तैयार कर सकता है।

इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में विकास के नए युग का होगा सूत्रपात: डॉ. यादव

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड परियोजना किसान और सरकार के बीच विश्वास की बनेगी मिसाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड के किसानों के हित में जमीनी स्तर पर मार्ग निर्माण को स्वीकृति और उचित मुआवजे की व्यवस्था किए जाने पर इंदौर जिले के सावेर क्षेत्र के निवासियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया।

डॉ. यादव को पगड़ी और बड़ी माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे सभी लोगों को होली और रंगपंचमी की बधाई दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से इंदौर और उज्जैन के बीच बनने वाली सड़क से इंदौर और उज्जैन का सफर सवा घंटे की जगह आधे घंटे का रह जायेगा। दोनों शहरों के बीच तेज कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्थानीय स्तर पर उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, किसानों को मण्डियों तक पहुंच और



व्यापारियों तथा उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह मार्ग, देश के व्यापार व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के बीच इस मार्ग से यात्रा सुगम और कम समय में होगी। परिणामस्वरूप आवागमन बढ़ेगा और देश में इंदौर-उज्जैन क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ेगा।

डॉ. यादव ने कहा कि पारम्परिक और ऐतिहासिक रूप से इंदौर और उज्जैन के बीच इस

मार्ग का ही उचित उपयोग होता था। इस मार्ग से इंदौर के 20 और उज्जैन के 6 गांव लाभान्वित होंगे। सिंहस्थ के लिए भी यह मार्ग सुविधाजनक और उपयोगी होगा। इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में विकास की दृष्टि से नए युग का सूत्रपात हो रहा है। राज्य सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। किसानों के सुझावों के अनुसार इस मार्ग का निर्माण कराना और उसके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करना इस बात का

परिचायक है कि सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। यह परियोजना किसान और सरकार के बीच विश्वास की मिसाल बनेगी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग को इस रूप में स्वीकृति मिलना उनकी संवेदनशीलता का ही परिणाम है। किसानों को इस परियोजना में अब 816 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की जाएगी।

मऊगंज में छात्रावास घोटाले की ईओडब्ल्यू करेगा जांच निलंबित वार्डन के खिलाफ 89 लाख की अनियमितता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रावास में आर्थिक अनियमितताओं के मामले में निलंबित वार्डन के खिलाफ अब ईओडब्ल्यू जांच करेगा। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने इस संबंध में ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर विधिसंगत जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जांचकार के अनुसार छात्रावास की तत्कालीन अधिकािका श्रीमती शकुंतला नीरत को छात्रावास में अनियमितताओं के आरोपों के चलते 22 जनवरी को निलंबित किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय दल गठित किया गया था। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में छात्रावास संचालन में 89 लाख 61 हजार 607 रुपये की आर्थिक अनियमितता पाई है।

जांच में सामने आया कि भंडार सामग्री को खरीद के लिए नियमानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके कारण प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त नहीं हो सकीं और शासकीय धन को नुकसान पहुंचा। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी अधिकारी ने

वार्डन के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ कर दी है और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को भेज दिया गया है।

बताया जा रहा है कि निलंबन के बाद वार्डन के समर्थन में कुछ संगठनों और नेताओं ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान कलेक्टर और कलेक्टर कर्मचारियों पर भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। कई दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन के चलते प्रशासन को कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी को भी हटाना पड़ा था।

हालांकि विरोध प्रदर्शन के बावजूद जांच प्रक्रिया जारी रही और जांच टीम ने वार्डन के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की। बताया गया है कि संबंधित वार्डन लंबे समय से छात्रावास में पदस्थ थीं और उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आती रही थीं, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। नया जिला बनने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जाएगी।

जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर ने जनता को लगातार...

महंगाई का डोज दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी 'डॉक्टर' की उपाधि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: घरेलू रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये की वृद्धि की गई है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के विरोध में भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतर आई।

शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में द्वारा रोशनपुरा चौराहे पर घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में ₹.60 एवं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 115 रुपए की की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से 'डॉक्टर' की उपाधि दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी जी का प्रतीकात्मक कटआउट बनाकर विरोध दर्ज कराया गया, जिसमें उन्हें महंगाई का 'डोज' देते हुए दर्शाया गया।

उन्होंने सरकार से जल्द कीमतें कम करने की मांग की। भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि वर्ष 2014 में



शहर	पहले	अब (अनुमानित)
भोपाल	858.50	918.50
इंदौर	881.00	941.00
जबलपुर	859.50	919.50
ग्वालियर	936.50	996.50
उज्जैन	912.50	972.50

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 400 रुपए थी, जो अब बढ़कर 900 रुपए से अधिक हो गई है। उनका आरोप है कि महंगाई

हर क्षेत्र में बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं

किए गए तो कांग्रेस आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी।

इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अमित शर्मा, कोलार ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़, पूर्व जिला युवक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, अधिनवन बरौलिया, राजकुमार सिंह, मुजाहिद सिद्दीकी, सुशील प्रजापति, दीपू तोमर, टी आर गेहलोत, सोनू तोमर, महक राणा, वरिष्ठ कांग्रेस जन पदाधिकारी गण, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व नागरिक उपस्थित रहे।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल: वर्किंग वुमेन हॉस्टल

नप्र, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य परिवेश को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किरायाहीन आवास उपलब्ध कराने हेतु चार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

एमपीआईडीसी क्षेत्र में भारत सरकार की स्क्रीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस 2024-25 के तहत कुल 26 आवासीय ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 222

बेड्स होंगे। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 5700 से अधिक कार्यशील महिलाओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवास सुविधा मिलेगी।

वर्किंग वुमेन हॉस्टल विक्रम उद्योगपुरी (उज्जैन), पीथमपुर सेक्टर-1 और 2 (धार), मालनपुर-धिरांगी (भिंड) और मंडीडीपा (रायसेन) में विकसित किए जा रहे हैं। करीब 6.66 हेक्टेयर भूमि पर इन परियोजनाओं की लागत लगभग 250 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि ये हॉस्टल महिलाओं को कार्यस्थल के निकट सुरक्षित आवास, बेहतर जीवन सुविधा और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देंगे।

विकास पर बजट का 41 प्रश ही खर्च सरकार सिर्फ सुर्खियों में व्यस्त: पटवारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की भाजपा सरकार पर ग्रामीण विकास योजनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जबकि सरकार केवल सुर्खियों बटोरने में व्यस्त है।

श्री पटवारी शनिवार को अपने बयान में कहा कि सरकार बजट प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बेहद लापरवाह साबित हो रही है। केंद्र और राज्य के सहयोग से संचालित कई योजनाओं के लिए पर्याप्त

बजट आवंटित होने के बावजूद उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे ग्रामीण विकास की योजनाएँ जमीनी स्तर पर प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 27,745.18 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था, लेकिन 7 मार्च 2026 तक इसमें से केवल 11,457.66 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं, जो कुल बजट का करीब 41.30 प्रतिशत है। पटवारी के मुताबिक यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार की प्राथमिकता विकास नहीं, बल्कि घोषणाएँ और प्रचार है।

श्री पटवारी ने कहा कि यदि

ग्रामीण विकास की योजनाओं पर ही पर्याप्त खर्च नहीं होगा तो गांवों में रोजगार, सड़क, आवास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कैसे होगा। उनका आरोप है कि सरकार की लापरवाही, आर्थिक कुप्रबंधन और बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण कई योजनाएँ धरातल तक पहुंचने से पहले ही प्रभावित हो जाती हैं। उन्होंने भाजपा सरकार से मांग की कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि गांवों, किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

उदोतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आवासीय भवनों का काम संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार जय कैला देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने तथा कंसल्टेंट मेसर्स एनोविस कंसल्टेंट इंडिया प्रा. लि. के खिलाफ कार्रवाई और वसूली के निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

बैठक में 20 अन्य निर्माण कार्यों में सुधार करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को पूर्व निरीक्षणों के पालन, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और पुल-पुलियों के मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया गया। नए सड़क निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण और कोड जारी करना अनिवार्य किया गया।

पीएचक्यू में अग्नि सुरक्षा जागरूकता और मॉक ड्रिल का आयोजन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय में विशेष प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखते हुए प्रभावी तरीके से आग पर नियंत्रण करना सिखाना था। शनिवार सुबह आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षार्थियों को

आधुनिक अग्निशमन उपकरणों के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें तरल पदार्थों में लगी आग को सुरक्षित तरीके से बुझाने की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। सुरक्षार्थियों ने धुएं और लपटों के बीच सुरक्षित रहते हुए आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। इस दौरान मानसवी डीएसपी मोहनलाल मेहरा, पुलिस मुख्यालय सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक मुकेश सैनी और पुलिस फायर स्टेशन मंत्रालय की टीम मौजूद रही। अग्निशमन में उपयोग होने

वाले कई आधुनिक उपकरणों जैसे फोम नोजल, फायरमैन हेलमेट, अग्निशमन सिलेंडर, ब्रीदिंग ऑपरटर सेट, फायर ब्लैंकेट, लाइफ जैकेट, हौज पाइप और अन्य सुरक्षा उपकरणों की जानकारी दी गई कि आग मुख्यतः पांच प्रकार की होती है। लकड़ी और कोयले में लगी आग को क्लास ए, तरल पदार्थों की आग को क्लास बी, गैस से लगी आग को क्लास सी, धातु से लगी आग को क्लास डी और विद्युत आग को क्लास ई श्रेणी में रखा जाता है।

कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर...

जीतू पटवारी के होली मिलन समारोह स्थगित करने की मांग की

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई 35 से अधिक मौतों के बाद प्रदेश कांग्रेस में संवेदनशीलता को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर भोपाल में प्रस्तावित होली मिलन समारोह को स्थगित करने की मांग की है।

राकेश सिंह यादव ने शनिवार को लिखे अपने पत्र में कहा कि भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई मौतों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और कई परिवार

अभी भी गहरे शोक में हैं। ऐसे समय में जब शहर दुख और सदमे से गुजर रहा है, तब उत्सव मनाना जनता की भावनाओं के विपरीत संदेश दे सकता है।

पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृहनगर इंदौर है और वहां इस घटना के बाद शोक का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना अधिक जरूरी है। राकेश सिंह यादव ने कहा कि भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर प्रस्तावित होली मिलन समारोह को



लेकर जनमानस में सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि इसी घटना के विरोध में इंदौर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने

प्रदर्शन भी किया था, जबकि कई नेताओं ने इस बार होली से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह

किया कि पार्टी की मानवीय और संवेदनशील परंपरा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस होली मिलन समारोह को स्थगित करने की सलाह दी जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को यह महसूस हो सके कि कठिनाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जलकांड को लेकर जहां एक ओर प्रदेश सरकार पहले से विपक्ष के निशाने पर है, वहीं अब कांग्रेस के भीतर से उठी यह आवाज संगठन की कार्यशैली और संवेदनशीलता को लेकर नए सवाल खड़े कर रही है।